Useful For Prelims

Date: 28 December 2025

गुजरे कल और आज के बदलते हालात की तुलना करें, तो क्या चेतावनी की कुछ नई अनुगूंजें आपको नहीं सुनाई पड़ उठतीं? इस गुजरते सन् 2025 में भले ही हमने 21वीं सदी की रजत जयंती मनाई, पर स्वर्ण जयंती को चमकदार बनाने के लिए जरूरी है कि बिगड़ते पर्यावरण को संभालने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। सन् 2026 के समक्ष बड़ी चुनौती भी यही है।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

सिंधु सभ्यता के कुछ सबक

शशि शेखर

आजकल

सौ साल पहले अमेरिका के मशहूर न्यायविद बेंजामिन एन कार्डोजो ने एक मार्के की बात कही थी- 'इतिहास अतीत को रोशन करते हुए वर्तमान को आलोकित करता है और वर्तमान को प्रकाशित कर भविष्य को प्रदीप्त करता है।'

बेंजामिन साहब को श्रद्धांजलि देते हुए क्यों न आज के धुआं-धुआं वर्तमान की समीक्षा की जाए?

साल 2025 के अंतिम सप्ताह की शुरुआत जबर्दस्त जद्दोजहद से हुई थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अरावली पर्वतमाला को लेकर उबले पड़ रहे थे। वजह? 20 नवंबर, 2025 को देश की आला अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल वे पर्वतमालाएं ही अरावली मानी जाएंगी, जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं। यह फैसला हुकूमत के इस तर्क पर आधारित था कि प्रशासनिक 'स्पष्टताओं' के लिए एक निश्चित परिभाषा की जरूरत है, ताकि विकास योजनाएं बनाई जा सकें। फैसले के विरोधी इसे अरावली के लिए 'डेथ वारंट' के विशेषण से नवाज रहे थे।

उनका कहना था कि इस निर्णय से अरावली पर्वतमाला का 90 फीसदी हिस्सा खतरे में आ जाएगा। बात बिगड़ती देख देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया कि यह सिर्फ गलतफहमी है। खनन के लिए 0.19 प्रतिशत हिस्सा ही खुला रहेगा। इससे समूची पर्वतमाला, यहां के वन और वन्य-जीवन को कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बावजूद आशंकाओं का बाजार गर्म रहा। आखिरकार, 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी देने पर रोक लगा दी। इस आशंका का इससे बेहतर पटाक्षेप भला और क्या हो सकता था? बताने की जरूरत नहीं कि यह अरावली ही है, जो थार के रेगिस्तान का बढ़ाव रोककर उत्तर भारत के बड़े हिस्से को शस्य श्यामला बने रहने की स्थितियां मुहैया कराती है।

इसके बावजूद इस इलाके की हालत बेहद खराब है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई साल से उत्तर भारत के लोगों को एक भी दिन साफ हवा नसीब नहीं हुई। देश की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की हालत तो और भी खराब है। गुजरे एक साल में यहां ग्रैप-3 अथवा ग्रैप-4 की पाबंदियां 40 दिन, यानी एक महीने से ज्यादा लागू रहीं। इस भयावह आंकड़े में अभी बढ़ोतरी ही होनी है, क्योंकि इन पंक्तियों के लिखे जाते वक्त भी ग्रैप-3 लागू है।

दिल्ली शहर जान-बूझकर यमुना के किनारे बसाया गया था, ताकि यह सदानीरा यहां के बाशिंदों को सदा-सर्वदा साफ पानी मुहैया करा सके, लेकिन इसका जल आचमन तो दूर, स्नान तक के काबिल नहीं रह बचा है।

कोई आश्चर्य नहीं कि साफ हवा-पानी के अभाव में लोग दिल्ली और एनसीआर छोड़कर भागने के जतन करने लगे हैं। रियल स्टेट मार्केट रिसर्च कंपनी 'सैविल्स इंडिया रिसर्च' के अनुसार, गोवा में नए 'विला' की कीमतें सात से दस करोड़ रुपये के बीच हैं, जो दक्षिण दिल्ली और दक्षिण मुंबई के शानदार 'अपार्टमेंट्स' के बराबर है। मेट्रो शहरों की भागदौड़ और प्रदूषण से त्रस्त लोग यहां सुकून भरी जिंदगी के लिए आ रहे हैं। यही वजह है कि इस शांत समुद्री सूबे में आवासीय भूमि के दामों में साल-दर-साल 65 फीसदी तक की वृद्धि देखी गई है।

गोवा अकेला नहीं है। दून घाटी में बसे देहरादून में दो साल के भीतर जमीनें औसतन 22 फीसदी महंगी हो गई हैं। शहर के संभ्रांत इलाकों में तो 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही स्थिति नैनीताल, हरिद्वार की है। महानगर कोई भी हो, उसके समीप बसे मनोरम गांव-कस्बों का यही हाल है।

यह स्थिति यकीनन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर इतनी भीड़ सम्हालने की क्षमता नहीं रखता। इस पलायन के कुछ और खतरे भी हैं।

मैं आपका ध्यान 'कम्यूनिकेशन्स अर्थ ऐंड एनवायर्नमेंट' में प्रकाशित एक अध्ययन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस शोध में हम भारतीयों की आदि, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षरण के कारणों का खुलासा किया गया है। हमारे पूर्वजों ने ईसा से छह हजार साल पहले इसे उस वक्त जतनपूर्वक गढ़ना शुरू किया था, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कबीलों और जंगलों में सिमटा हुआ था। हमारे पुरखों के बनाए हड़प्पा और मोहन जोदड़ो जैसे शहरों की एक-दूसरे को काटती सड़कें, पक्की नालियां, जल निकासी और पक्की ईंटें लोगों को हैरत में डाल देती हैं।

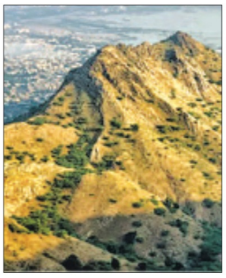

सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों में उन्नत खेती और अन्न भंडारण के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस सभ्यता के लोग पर्यावरणवादी थे। उनके शहर सागर और नदी किनारे बसाए गए। वहां प्रकृति संरक्षण के तमाम इंतजामात किए गए। प्रकृति और मानवीय क्षमता की यह सभ्यता अनुपम मिसाल थी।

भरोसा न हो, तो एक बार गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा देख आइए। वहां तीन चरणों में संचित जल को बालू से साफ किया जाता था। अंग्रेजों ने बाद में इस तकनीक का इस्तेमाल देश के कई शहरों में किया। यकीन न हो, तो शिमला चले जाइए। वहां एक संरक्षित क्षेत्र है- कैचमेंट एरिया। गोरे सत्तानायकों ने सिंधु सभ्यता की तर्ज पर ही यहां जल भंडारण और शोधन के इंतजामात किए। आज भी हिमाचल की राजधानी के बड़े हिस्से को यहीं से पानी मिलता है।

सवाल उठता है कि जो सभ्यता इतनी संपन्न और विचारशील थी, वह समाप्त कैसे हो गई?

इसे लेकर विदेशी आक्रमण, भूकंप, बाढ़, सूखे आदि के सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते रहे हैं। यह नई रिसर्च एक अछूते पहलू पर रोशनी डालती है। इसके अनुसार, नगरों के विस्तार के साथ वहां पनपती दुश्वारियों के कारण सैन्धव वासियों ने सुदूर गांवों और छोटे कस्बों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इससे सिंधु घाटी के नगर आव खोते गए। समूची सभ्यता के पतन के कई और कारणों में से एक यह भी है।

क्या यह प्रक्रिया धीमे-धीमे पुनर्जीवित हो उठी है?

कोविड-19 के बाद से भारत के साथ यूरोप और अफ्रीका के तमाम देशों अथवा महानगरों से पलायन का दौर तेज हो गया है। यह पहला मौका है, जब इटली के शहरों कैम्माराटा, ओलोलाई, लोकाना आदि के बारे में खबरें छप रही हैं कि यहां जो चाहे आकर निःशुल्क रह सकता है। बस उसे अपने आवास का रख-रखाव करना होगा। इटली अकेला नहीं है, यूरोप के कई देश भी इस बला की चपेट में हैं।

बेंजामिन एन कार्डोजो की बात मानते हुए गुजरे कल और आज के बदलते हालात की तुलना करें, तो क्या चेतावनी की कुछ नई अनुगूंजें आपको नहीं सुनाई पड़ उठतीं?

इस गुजरते सन् 2025 में भले ही हमने 21वीं सदी की रजत जयंती मनाई, पर स्वर्ण जयंती को चमकदार बनाने के लिए जरूरी है कि बिगड़ते पर्यावरण को संभालने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। सन् 2026 के समक्ष बड़ी चुनौती भी यही है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

Hindustan Page No-12

अंतरिक्ष में उत्सव जैसा नजर आता है तारे के अंत का सफर

जिस तरह साल 2025 अपने अंतिम दिनों में है, अंतरिक्ष की यह तस्वीर भी हमें एक भव्य अंत की कहानी दिखा रही है। जब तारे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होते हैं, तो वे अंतरिक्ष में गैस और धूल के ऐसे ही शानदार नेबुला बनाते हैं। यह नासा द्वारा ली गईं इस वर्ष की सबसे भव्य तस्वीरों में से एक है।

दुनिया भर में लू, जंगल की आग, सूखा और तूफान की मार | संकट | कैलिफोर्निया की आग से ज्यादा असर पड़ा

जलवायु परिवर्तन से 120 अरब डालर का नुकसान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

साल 2025 में दुनिया के कई देशों में तापमान बढ़ रहा है। भीषण गर्मी, जंगलों में आग लग गई, भारी बारिश, तूफान और बाढ़ से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लू, जंगल की आग, सूखा और तूफानों के कारण 2025 में दुनिया को 120 अरब अमेरिकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ है।

जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का विश्लेषण करने वाली एक नई रपट में यह जानकारी दी गई है। ब्रिटेन आधारित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'क्रिश्चियन एड' की रपट ने इस नुकसान को रेखांकित करते हुए कहा कि संकट को बढ़ाने में जीवाश्म ईंधन कंपनियों की केंद्रीय भूमिका रही है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में नवंबर में हुईं चक्रवात और बाढ़ की घटनाएं रहीं जिनसे 25 अरब अमेरिकी डालर का नुकसान हुआ और थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम तथा मलेशिया में 1,750 से अधिक लोग मारे गए।
रपट के अनुसार, तीसरे स्थान पर चीन में आई विनाशकारी बाढ़ रही, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए, 11.7 अरब अमेरिकी डालर का नुकसान हुआ और कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई।

रपट में कहा गया कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए तत्काल कदम उठाकर इन आपदाओं को टाला जा सकता था। 'इंपीरियल कालेज लंदन' की एमेरिटस प्रोफेसर जोआना हाई ने कहा कि ये आपदाएं प्राकृतिक नहीं हैं,ये जीवाश्म ईंधन के विस्तार और राजनीतिक देरी का परिणाम हैं। रपट के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान 122 अरब अमेरिकी डालर से भी अधिक रहा। इन आकलनों में से अधिकतर केवल उन घटनाओं से जुड़े नुकसान पर आधारित हैं जो बीमा के तहत कवर थे इसलिए वास्तविक आर्थिक नुकसान इससे भी अधिक होने की आशंका है। रपट में कहा गया कि 2025 में सबसे अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के लिहाज से अमेरिका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली 10 बड़ी घटनाओं में से कैलिफोर्निया की आग एकल रूप से सबसे बड़ी घटना रही, जिसमें 60 अरब अमेरिकी डालर का नुकसान हुआ और 400 से अधिक लोगों की मौत हुई।

सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण-पूर्व एशिया में नवंबर में हुईं चक्रवात और बाढ़ की घटनाएं रहीं जिनसे 25 अरब अमेरिकी डालर का नुकसान हुआ और थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम तथा मलेशिया में 1,750 से अधिक लोग मारे गए। रपट के अनुसार, तीसरे स्थान पर चीन में आई विनाशकारी बाढ़ रही, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए।

Jansatta Page No-7

देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा नोएडा, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 दिसंबर।

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहरों में प्रदूषण का जानलेवा स्तर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार को नोएडा 409 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया।

प्रदूषण की यह मार पड़ोसी शहरों पर भी बराबर दिखी, जहां गाजियाबाद 404 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 395 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ ग्रेटर नोएडा ने देश के तीसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

नोएडा में शनिवार को 409 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया।

दिसंबर महीने के बीते 27 दिनों के विश्लेषण से पता चलता है कि नोएडा में वायु गुणवत्ता सात दिन अधिक लाल श्रेणी यानी 400 से ऊपर रही, जबकि 16 दिनों तक यह 300 से अधिक के साथ लाल श्रेणी में बनी रही। पूरे महीने में केवल चार दिन ही ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार यानी नारंगी श्रेणी में दर्ज किया गया। इस बीच, प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है।

शनिवार को शहर में निरीक्षण के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन पाया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित पक्षों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

दिल्ली में 20 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 दिसंबर।

राजधानी में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं देखा गया है। धुंध और हवा की गति धीमी रहने के कारण शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 332 था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 20 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया। गंभीर श्रेणी वाले प्रमुख क्षेत्र शादीपुर, विवेक विहार, अशोक नगर, बावना, चांदनी चौक, डीटीयू, द्वारका, आइटीओ और मुंडका रहे। गुरुवार को शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। बुधवार और गुरुवार को हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही, लेकिन शुक्रवार से प्रदूषण फिर बढ़ने लगा और शनिवार को गंभीर स्तर के करीब पहुंच गया।

Jansatta Page No-10

सुविधा | बिहार के चार शहरों से अब लोगों को मिल रही हवाई सेवा, पटना का नया टर्मिनल भवन 1200 करोड़ की लागत से बना, क्षमता प्रतिवर्ष एक करोड़ यात्रियों की

पटना में बना आधुनिक एयरपोर्ट, पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार में इस वर्ष हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने से कोसी और सीमांचल के लोगों को राहत मिली। उन्हें हवाई सेवा के लिए सिलीगुड़ी या पटना जाने की अब जरूरत नहीं। वहीं, राजधानी के जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास हुआ।

इसके साथ ही राजधानी के बिहटा में 1400 करोड़ रुपये से बनने वाले नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बनने से हवाई जहाज की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल रही हैं। इसका उद्घाटन 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था।

नया टर्मिनल भवन 65,150 वर्गमीटर में बना है, जिसकी क्षमता एक साथ 3000 यात्रियों की है। पहले यह केवल 11,130 वर्ग मीटर में था। नए टर्मिनल भवन में उड़ानों की क्षमता 34 से बढ़कर 75 और यात्रियों की क्षमता सालाना 25 लाख से बढ़कर एक करोड़ हो गई। परिसर के अंदर प्रस्थान के लिए आठ और आगमन के लिए चार गेट बनाए गए हैं। इसके भूतल से यात्री बाहर और पहले तल से अंदर जाते हैं। 15 लिफ्ट और चार चलंत सीढ़ी लगाई गई है। वहीं यात्रियों के लिए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज भी लगाएं गए हैं।

15
सितंबर से पूर्णिया एयरपोर्ट पर सेवा शुरू होने से सीमांचल, कोसी के लोगों को राहत

पटना से बड़ा होगा बिहटा एयरपोर्ट

पटना एयरपोर्ट से बिहटा का एयरपोर्ट बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहटा एयरपोर्ट पर बनने वाले नये टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया था। इसके नए टर्मिनल भवन का निर्माण 68,000 वर्गमीटर में होना है। जो पटना एयरपोर्ट से 2850 मीटर अधिक है। इसमें अतिव्यस्ततम समय में 3000 यात्री एक साथ परिसर में रह सकेंगे।

बिहार का चौथा एयरपोर्ट बना पूर्णिया

पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट बना, जहां से कॉमर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू की गयी। इसका शुभारंभ 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिसके साथ ही सीमांचल का उड़ान भरने का सपना साकार हो गया। पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण करीब 46 करोड़ से किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा रनवे है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ान की हसरत अधूरी

बिहार में नियमित तौर पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2025 में नई नीति लाई गई। इसके बाद राज्य सरकार और विमानन कंपनियों के बीच वार्ता भी हुई लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण लोगों को 2026 में सुविधा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार काठमांडू के लिए पटना और गया से विमान सेवा शुरू करेगी। इन दोनों जगहों से काठमांडू के लिए छोटी विमान सेवा शु होगी। इसके अलावा गया से शारजाह या फुजैरा, बैंकाक, सिंगापुर और कोलंबो के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या निविदा आमंत्रण सूचना के माध्यम से विमान कंपनियों का चयन होगा।

Hindustan Page No-2

देशभर में एंबुलेंस का 112 नंबर होगा

देशभर के राजमार्गों पर अब 10 मिनट में एंबुलेंस पहुंच जाएगी। केंद्र ने जीपीएस आधारित बेसिक लाइफ सपोर्ट रूटमैप तैयार किया है। इसके तहत राज्य एंबुलेंस सेवाओं 108 का आपात सेवा 112 में विलय किया जाएगा।

जेट की रफ्तार से दौड़ी चीन की ट्रेन, दो सेकेंड में पकड़ी 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

- 400 मीटर ट्रैक पर हुआ सफल परीक्षण, सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट से मिली उड़ान जैसी गति
- भविष्य के हाइपरलूप और अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक को मिल सकती है नई दिशा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: चीन ने जेट विमान की रफ्तार से दौड़नेवाली ट्रेन का परीक्षण किया है। दावा किया गया है कि इस ट्रेन ने दो सेकेंड में ही 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। ये कुछ ऐसा है, जैसे दिल्ली से पटना की दूरी डेढ़ घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली जाए। परीक्षण का वीडियो सामने आने के बाद यह प्रयोग दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में ट्रेन इतनी तेज नजर आती है कि वह पलक झपकते आंखों से ओझल होती प्रतीत होती है और पीछे धुंध जैसी लकीर छोड़ जाती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी आफ डिफेंस टेक्नोलाजी (एनयूडीटी) के शोधकर्ताओं ने 400 मीटर लंबे विशेष मैगलेव ट्रैक पर लगभग एक टन वजनी सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव वाहन का परीक्षण किया। इसे

जेट विमान की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन
• सौजन्य इंटरनेट मीडिया

सुरक्षित तरीके से उच्चतम रफ्तार पर पहुंचाने के बाद नियंत्रित ढंग से रोका भी गया।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेशन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। परियोजना से जुड़े प्रोफेसर ली जी ने कहा कि यह उपलब्धि चीन में अल्ट्रा-हाई-स्पीड मैगलेव परिवहन के अनुसंधान और विकास को नई गति देगी। इस टीम ने पिछले 10 वर्षों से इस तकनीक पर काम किया है और इसी साल जनवरी में 648 किमी प्रति घंटा की गति हासिल की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी तेज गति वाली मैगलेव तकनीक से भविष्य में दूर-दराज के शहरों को कुछ ही मिनटों में जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा, यह तकनीक हाइपरलूप जैसी अवधारणाओं को भी व्यावहारिक रूप देने में सहायक हो सकती है, जहां वैक्यूम ट्यूब के भीतर ट्रेनें अत्यंत तेज गति (लगभग 1000 किमी प्रति घंटा) से चलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेशन का उपयोग राकेट और विमानों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकता है, जिससे ईंधन की खपत और लागत कम होने की संभावना है।

Dainik Jagaran Page No-14

भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश : वैष्णव

नई दिल्ली, आइएनएस: केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि भारत ने इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन को छह गुना बढ़ा दिया है और अब यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कई पोस्ट में वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रानिक निर्यात को आठ गुना बढ़ाने में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएलआइ योजना ने 13,475 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जिससे इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन संभव हुआ है। इससे निर्माण, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिला है। पिछले पांच वर्षों में 1.3 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है और इलेक्ट्रानिक्स अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गई है, जो पहले सातवें स्थान पर थी। वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग में 249 आवेदन मिले हैं। इनमें 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश, 10.34 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और 1.42 लाख नौकरियों के सृजन के प्रस्ताव है।

अश्विनी वैष्णव

- **इलेक्ट्रानिक्स निर्यात बढ़ाने में पीएलआइ का महत्वपूर्ण योगदान**
- **योजना ने 13,475 करोड़ से ज्यादा निवेश आकर्षित किया**

Dainik Jagaran Page No-11

2026 में एफडीआइ में मजबूत बढ़ोतरी होने की उम्मीद

मजबूत व्यापक आर्थिक आधार, बड़ी निवेश घोषणाओं, ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के प्रयासों का मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र: आगामी कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रवाह में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। इसमें मजबूत व्यापक आर्थिक आधार, बड़ी निवेश घोषणाओं, ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों और निवेश से जुड़े नए व्यापार समझौतों का प्रमुख योगदान रहेगा।

निवेशक अनुकूल नीतियां, निवेश पर मजबूत रिटर्न, प्रतिभाशाली कार्यबल, अनुपालन बोझ को कम करना, छोटे उद्योग से संबंधित अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना और सुव्यवस्थित अनुमोदन ऐसे प्रमुख उपाय हैं जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं। जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान कुल विदेशी निवेश 60 अरब डालर को पार कर गया है।

डीपीआइआइटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया का कहना है कि पिछले ग्यारह वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के कारण भारत ने उल्लेखनीय निवेश आकर्षित किए हैं। 2024-25 में यह 80.62 अरब डालर के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गया है। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष (2026) एफडीआइ पिछले वर्ष के 80.62 अरब डालर के आंकड़े को पार कर सकता है।

- मुक्त व्यापार समझौतों के जरिये बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश मिलने की संभावना
- वैश्विक टेक्नोलाजी कंपनियों के घरेलू विस्तार से भी भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा

60 अरब डालर के पार पहुंचा जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान एफडीआइ

80.62 अरब डालर एफडीआइ मिला भारत को वित्त वर्ष 2024-25 में

भारत में शीर्ष निवेशक

देश	हिस्सा (%में)
मारीशस व सिंगापुर	49
अमेरिका	10
नीदरलैंड्स	7.2
जापान	6
ब्रिटेन	5

2024 में 11 प्रतिशत घटा वैश्विक एफडीआइ

यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार, वैश्विक एफडीआइ प्रवाह 2024 में 11 प्रतिशत घटकर 1.5 ट्रिलियन डालर रहा है। हालांकि, यह आंकड़ा अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रदर्शन में व्यापक भिन्नताओं को छुपाता है। एफडीआइ प्रवाह में विकसित देशों में 22 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाह स्थिर रहा है। भारत में निवेशकों ने मजबूत परियोजना गतिविधि बनाए रखी है।

एफडीआइ आकर्षित करने वाले भारत के प्रमुख क्षेत्र

भारत में अधिकतम एफडीआइ आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं, कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास, आटोमोबाइल, रसायन और फार्मास्युटिकल्स शामिल हैं। दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्युटिकल्स और बीमा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लाटरी, जुआ और सट्टेबाजी, विट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय और तंबाकू का उपयोग करके सिगार और सिगरेट निर्माण में एफडीआइ प्रतिबंधित है।

भारत ने चार देशों के संगठन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है। इसके तहत इन चारों देशों ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डालर के निवेश का वादा किया है। यह समझौता एक अक्टूबर 2025 को लागू हुआ था। तब स्विस स्वास्थ्य सेवा प्रमुख रोश फार्मा ने अगले पांच वर्षों में भारत में 1.5 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 17,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने का वादा किया था। न्यूजीलैंड ने भी भारत के साथ व्यापार समझौते के तहत 20 अरब डालर का एक समान वादा किया है, जिसके 2026 में लागू होने की संभावना है।

कई बड़ी कंपनियों ने की निवेश की घोषणा : इस वर्ष कुछ प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने बड़े निवेश की घोषणाएं की हैं। माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने 2030 तक भारत में 17.5 अरब डालर के निवेश की घोषणा की है। दिग्गज ई-कामर्स कंपनी एमेजोन अगले पांच वर्षों में भारत में 35 अरब डालर के निवेश की योजना बना रही है। गूगल अगले पांच वर्षों में भारत में एक एआइ हब स्थापित करने के लिए 15 अरब डालर का निवेश करेगी। आइफोन निर्माता एपल और दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रानिक्स प्रमुख सैमसंग भी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। आर्सेलर मित्तल निप्पान स्टील इंडिया 2026 तक रंगीन कोटेड स्टील की क्षमता को वर्तमान सात लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य बना रही है।

Dainik Jagaran Page No-11

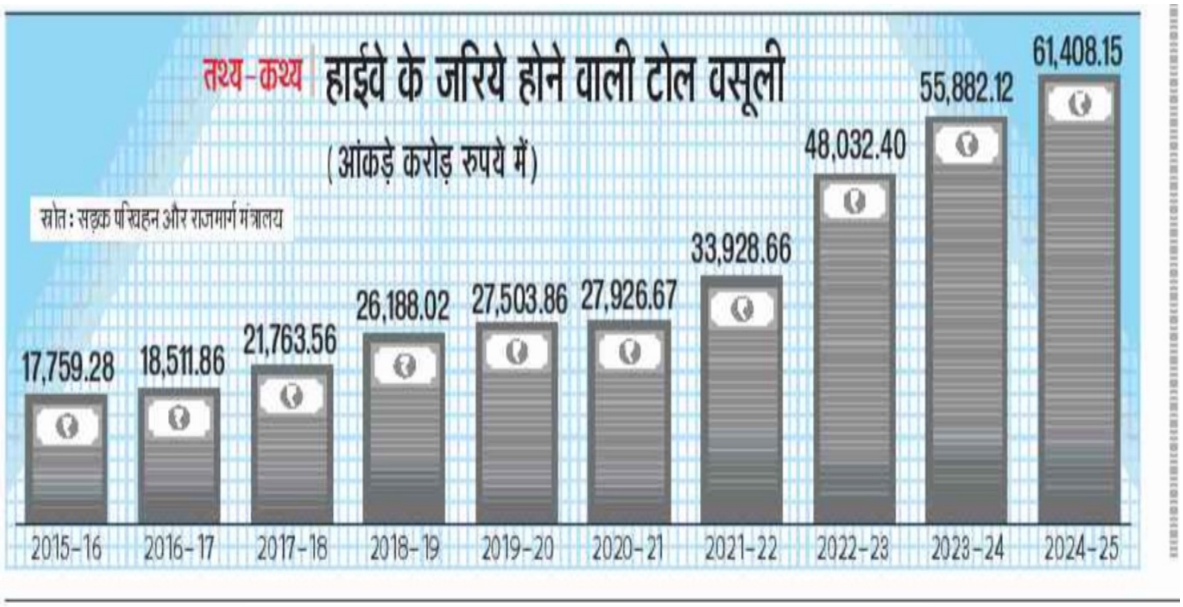

Dainik Jagaran Page No-8

नाखूनों में छिपे हैं कैंसर तक के संकेत

नाखून रोगों पर हो रहे 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन ओनिकोकान-2025 में जुटे विशेषज्ञ

प्रदेश में पहला अधिवेशन

जागरण संवाददाता, पटना : नाखून केवल सुंदरता का हिस्सा नहीं बल्कि कई गंभीर रोगों के शुरुआती संकेत भी देते हैं। नाखूनों में दिखने वाला रंग परिवर्तन, काली रेखाएं, मोटापन या बार-बार संक्रमण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है। नाखून शरीर का ऐसा हिस्सा है, जो सबसे पहले अंदरूनी बीमारियों का संकेत देता है, लेकिन आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। गलत इलाज और देरी से रोग गंभीर रूप ले लेता है। यह चेतावनी प्रदेश में पहली बार नाखून स्वास्थ्य (नेल हेल्थ) पर हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन ओनिकोकान-2025 में देश के प्रख्यात विशेषज्ञों ने दी। नेल सोसायटी आफ इंडिया (एनएसआइ) द्वारा आयोजित इस 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के त्वचा व नेल विशेषज्ञों ने नाखून संबंधी रोगों के विज्ञान, पहचान और उपचार के महत्व पर चर्चा की। नेल सोसायटी आफ इंडिया के अध्यक्ष डा. एस सच्चिदानंद व मानद सचिव डा. सुजाला ने एम्स पटना, पीएमसीएच, एनएमसीएच व आइएडीवीएल बिहार की टीम के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजन सचिव डा. अभिषेक कुमार झा, आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक डा. एमके सिन्हा, डा. विकास शंकर, डा. स्वेतलिना प्रधान, डा. श्रीपर्णा देव आदि की प्रशंसा की।

- नाखून संबंधी रोगों के विज्ञान और पहचान व उपचार के महत्व पर चर्चा
- नाखून ऐसा हिस्सा है, जो पहले अंदरूनी बीमारियों का संकेत देता

घर पर बरती जाने वालीं सावधानियां

- गंदे या नुकीले उपकरणों से नाखून नहीं काटें या कटवाएं।
- ज्यादा समय तक नेल पालिश ऐक्रेलिक नेल्स का प्रयोग नहीं करें।
- मधुमेह, उम्रदराज लोग नाखून की समस्याओं को हल्के में नहीं लें।
- किसी भी संदेह पर स्वयं दवा नहीं लें बल्कि चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें।

कब तुरंत चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें

- काली या गहरी एकल रेखा या धब्बा बढ़ रहा हो।
- नाखून में तेज़ दर्द, सूजन या मवाद
- अचानक नाखून का गिरना या अलग होना।
- डायबिटीज, बुजुर्ग या इम्यून कमजोर रोगी में नाखून रोग
- घरेलू दवा-क्रीम से लाभ नहीं हो रहा हो
- चोट के बाद ठीक न हो रहा नाखून।

रोग	नाखूनों में दिखने वाले लक्षण
फंगल इंफेक्शन	पीले, मोटे व टूटने वाले नाखून
सोरायसिस	गड्ढेदार सतह, मोटापन, लालिमा
बैक्टीरियल इंफेक्शन-पैरोनाइशिया	दर्द, सूजन, मवाद
ट्रामा-चोट से विकृति	काला पड़ना, टूटना
विटामिन-मिनरल की कमी	कमजोर, टूटने वाले नाखून
थायराइड- एनीमिया या लिवर रोग	नाखून का रंग व आकार बदलना
मेलानोमा- नेल ट्यूमर	कैंसर का जोखिम
काली रेखा, फैलता धब्बा, खून या दर्द	विशेष रूप से गंभीर संकेत

डर्मेटोलाजिस्ट ही नाखून रोगों के असली विशेषज्ञ

विशेषज्ञों ने कहा कि नाखूनों की बीमारियों के लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ ही सही डाक्टर होते हैं। डर्मेटोलाजिस्ट को नाखून से जुड़े रोगों की मेडिकल व सर्जिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बायोप्सी, ट्यूमर व संक्रमण का इलाज शामिल है। डा. अर्चना सिंघल, डा. चंदन ग्रोवर, डा. सुशील महिलियानी, डा. वीनीत रेहलान, डा. शिखा बंसल जैसे राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने एम्स पटना में हुई कार्यशाला व एक होटल में आयोजित वैज्ञानिक सत्र, लाइव डेमो व हैंड्स-आन वर्कशाप के द्वारा नाखून रोगों के आधुनिक इलाज की जानकारी दी।

रोग का खतरा कम करने के उपाय

- नाखून सूखे और साफ रखें, तंग जूते नहीं पहनें
- नेल-कटिंग के लिए स्टीरल, साफ उपकरण का प्रयोग करें।
- सार्वजनिक सैलून में हाइजीन सुनिश्चित करें
- बार-बार नेल-पालिश, नेल-एक्सटेंशन से बचें
- हाथ-पैर देर तक गीले नहीं रखें

Dainik Jagaran Page No-6

राजधानी सहित 17 शहरों की हवा रही प्रदूषित

जागरण संवाददाता, पटना : राजधानी सहित 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। शहर के गांधी मैदान का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआइ 148 दर्ज किया गया है। जबकि, राज्य में अररिया की हवा सबसे खराब रही। यहां का एक्यूआइ 191 दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे अधिक रहा।स्वच्छ और संतोषजनक श्रेणी में किसी शहर की हवा दर्ज नहीं हो सकी। विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ के कारण प्रदूषक वातावरण में कम एकत्रित हुए। इसके कारण प्रदूषित हवा के आंकड़ों में कमी आई है। पटना के सभी प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सभी जगहों पर प्रदूषित हवा की श्रेणी मध्यम स्तर की रही। शनिवार को अधिकतर शहरों में पीएम 2.5 एवं पीएम 10 की मात्रा मानक से ज्यादा रही।

*****

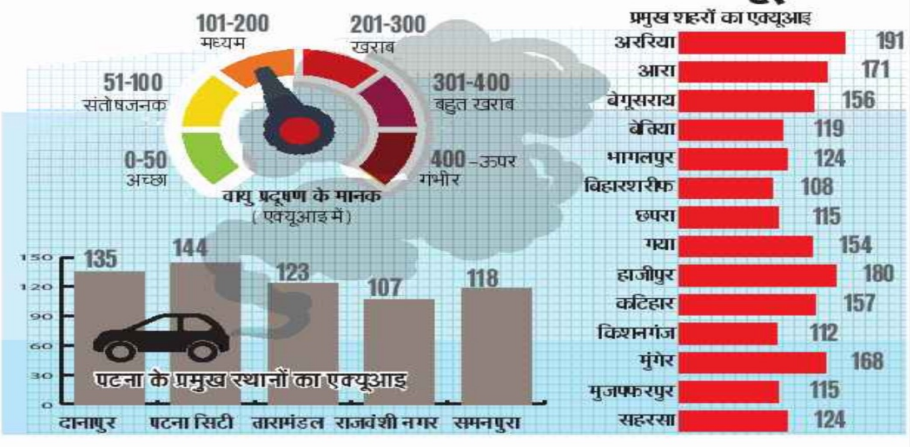

Dainik Jagaran Page No-4

कथनी और करनी

बाखबर

सुधीश पचौरी

> चैनलों की 'प्रदूषण कथा' ने दिल्ली के 'डबल इंजनों' को पहले ही रक्षात्मक बना रखा था कि अचानक एक दिन हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत देकर उत्तर प्रदेश सरकार को और भी रक्षात्मक बना दिया और जमानत पर कई सवाल उठे।

राहुल भाई जर्मनी में कह दिए कि भारत में संस्थान खत्म किए जा रहे हैं... वोट की चोरी हो रही है। प्रत्यारोप आया कि वे विदेश में भारत को बदनाम करने जाते हैं! ऐसे ही खबर आई कि तमिलनाडु में एक 'दीपम भक्त' ने खुद को आग लगा ली। कई चर्चक कहते रहे कि हिंदुओं को अपने ही देश में अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं। एक चैनल ने ताना मारा कि 'इको सिस्टम' खामोश... गाजा के लिए आंसू, बांग्लादेश में दो-दो हत्या पर चुप्पी! ये दोहरा पैमाना क्यों? इसी बीच एक चैनल ने प्रदूषण पर एक बेहतरीन 'पैरोडी' के जरिए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उसके बोल रहे कि 'फ्राड हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कहे हाय.. हाय कोई तो बताए क्या होगा..!' इधर 'आप' ने घेरा, उधर कुछ गैरसरकारी संगठनों और चैनलों ने सरकार को घेरा... दिल्ली की मुख्यमंत्री को घेरा। पहले अरावली के उजाड़ को लेकर घेरा, फिर प्रदूषण को लेकर घेरा कि दिल्ली गैस चेंबर बनी और कोई कुछ नहीं कर रहा।

बहरहाल, इन दिनों जब-जब धर्म की हानि होने लगती है, तब-तब एकाध 'भागवत वाणी' भक्तों को सहारा देती है। इस बार भी 'भागवत वाणी' हुई कि संघ को भाजपा के चश्मे से न समझें। संघ को संघ के चश्मे से देखें। यानी संघ भाजपा नहीं है, उससे कहीं 'बड़ा' है और कुछ 'हटकर' है। फिर एक दिन खबर आई कि कोलकाता में एक पाश्चात्य संगीत की एक गायिका को 'जागो मां जागो' गाने से रोका गया। इसे देख एक चर्चक बोला कि क्या 'माता' के राज्य में भी 'जागो मां जागो' नहीं गाया जा सकता? ये कैसा 'जनतंत्र' है?

इसी बीच महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के पहले चरण के चुनावों में एक ओर भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया तो दूसरी ओर विपक्ष हाशिये पर आता दिखा। शायद इसीलिए चुनावों के दूसरे चरण के लिए दोनों ठाकरे बंधु एकजुट हो रहे हैं। इसी क्रम में एक दिन तेलंगाना से खबर आई कि सरकार जल्द ही 'नफरती भाषण' के खिलाफ कानून लाने वाली है। भाजपा प्रवक्ता कहिन कि इसे विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बीच केरल में एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। कुछ ने कहा कि मारने वाले 'हिंदू वादी' थे, तो कुछ ने कहा कि उनको फंसाया गया है।

फिर एक दिन जैसे ही प्रियंका गांधी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, वैसे ही एक एंकर ने कहा कि एक ओर कांग्रेस सीएए का विरोध करती है, दूसरी ओर प्रियंका हिंदुओं को बचाने की गुहार लगाती हैं। प्रियंका की शायद ऐसी बातों से संकेत लेकर कई चैनलों ने राहुल भाई से उनकी तुलना शुरू कर दी। कई चर्चकों ने कहा कि बहन बेहतर... एक ने कहा कि उनके पास अपनी दादी का करिश्मा है।

यों तो चैनलों की 'प्रदूषण कथा' ने दिल्ली के 'डबल इंजनों' को पहले ही रक्षात्मक बना रखा था कि अचानक एक दिन हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत देकर उत्तर प्रदेश सरकार को और भी रक्षात्मक बना दिया और जमानत पर कई सवाल उठे। उन्नाव की बलात्कार पीड़िता ने स्वयं कई चैनलों पर आकर अपनी व्यथा कथा रो-रोकर कही और न्याय की मांग की। एक एंकर ने पूछा भी कि क्या निर्भया कानून किसी अदालत को ऐसा 'न्याय' करने की इजाजत देता है?

इसी बीच कई चैनलों पर कई राज्यों में आबादी की संरचना बदलने की खबरें चर्चा में रही। अब तक बंगाल, असम, झारखंड आदि में ही 'डेमोग्राफी' बदलने की बात थी, अब महाराष्ट्र खासकर मुंबई में 'जनसंख्या बदल' की चर्चा ने चर्चकों को 'हिंदू मुसलिम' में बांटे रखा। कई चर्चक इस बात से चिंतित दिखे कि अगर अब भी न समझे, तो देश के कई राज्य और शहरों में एक दिन हिंदू 'अल्पसंख्यक' बन जा सकते हैं।

इसी बीच उत्तर प्रदेश के नगर में भाजपा के कोई चालीस ब्राह्मण विधायक 'सहभोज' के लिए एकत्र हुए तो कई संवाददाता आयोजक से टोह लेने पहुंचे कि क्या यह मात्र 'सहभोज' था कि कुछ 'राजनीतिक भोज' था? जवाब में आयोजक ने यही कहा कि 'सहभोज' को 'सहभोज' ही रहने दो, कोई नाम न दो।

ऐसे ही, क्रिसमस के दिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के 'सेंट केथेड्रल चर्च' में जाकर 'क्रिसमस' मनाया, तो विपक्ष ने इसे ईसाई वोटों की कवायद बताया। तिस पर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा क्रिसमस मनाते लोगों को डराने-धमकाने की खबरों ने प्रधानमंत्री की गतिविधियों पर पानी फेरने की कोशिश की। एक अंग्रेजी चैनल ने अपने शाम की बहस के कार्यक्रम में बताया कि एक ओर प्रधानमंत्री चर्च जाकर एकता का संदेश देते रहे, दूसरी ओर कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में गिरजाघरों के आगे उपद्रव करते रहे... हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। नतीजा यह हुआ कि एक चैनल चर्चा में कि एक हिंदू प्रवक्ता तक एंकर के ऐसे सवालों के संतोषजनक जवाब न दे सके!

Jansatta Page No-16

सोच में संशोधन

संदर्भ

राकेश सिन्हा

> कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना तात्कालिक आवश्यकता है, मगर बंगाली अस्मिता को समृद्ध करने की योजना को गैर-राजनीतिक एवं गैर सांप्रदायिक तरीके से लागू करना दीर्घकालिक समाधान है। समय के साथ सोच में संशोधन ही संकल्पित लक्ष्य तक पहुंचता है। बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वास्तव में भारत की उपराष्ट्रीयता है। मगर भारत की धर्मनिरपेक्षवादी राजनीति हमारी अपनी संस्कृति और दर्शन का खंडित रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बेरोक-टोक हो रही है। यह माना जाता है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कोई कारण होता है, मगर यह अकारण हो रहा है। इसके पीछे न तो व्यावसायिक, न ही राजनीतिक या किसी अन्य प्रकार की प्रतिद्वंद्विता है। यह कई दशकों से सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तभी तो 1951 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां हिंदुओं की जनसंख्या बाइस फीसद से घटकर 2022 में छह फीसद से भी कम रह गई है। ढाका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक अब्दुल बरकत ने अपनी पुस्तक 'रिफार्मिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड वाटर बाडीज इन बांग्लादेश' में बताया है कि वर्ष 1991 से 2001 और 2001 से 2012 के बीच क्रमशः 767 और 774 हिंदू प्रत्येक दिन 'गायब' होते रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि इस दौरान पांच लाख से अधिक हिंदू मारे गए या उनका धर्मांतरण हुआ अथवा उन्हें देश की सीमा से बाहर कर दिया गया।

पाकिस्तान में तो पहले ही गिने-चुने हिंदू रह गए हैं और अफगानिस्तान में उनका नामोनिशान नहीं बचा है। वर्ष 1909 में कर्नल यूएन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'ए डाइंग रेस' में हिंदू को मृतप्राय नस्ल बनने के आसन्न खतरे की चेतावनी दी थी। तब उसका संदर्भ हिंदुओं और मुसलमानों की प्रजनन दर में अंतर के कारण दोनों के बीच जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन था। मुखर्जी के सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण में कई पहलुओं को उजागर किया गया था। उन्होंने हिंदुओं के पढ़े-लिखे, धनाढ्य और कथित उच्च वर्गों में कम पढ़े-लिखे गरीब तथा कथित निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता और उदासीनता को भी इस गिरावट में एक कारण बताया है। यह भारत के लिए कुछ हद तक अब भी प्रासंगिक है। मगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का मृतप्राय नस्ल बनने का कारण लक्षित सांप्रदायिक हिंसा है। नेहरू-लियाकत समझौता (1950) बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। इसने अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी उनके अपने-अपने देशों पर छोड़ दी। सांप्रदायिक जुनून के आधार पर बने पाकिस्तान में 'साझी संस्कृति' या 'साझी राष्ट्रीयता' की कल्पना करना स्वयं को धोखा देना था। वह जुनून वहां अमरबेल की तरह पसरता गया। तभी तो वर्ष 1950 में पाकिस्तान के तत्कालीन कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल हिंदुओं पर अत्याचार से आहत होकर और अपने आपको असमर्थ पाकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भारत आ गए थे।

वर्ष 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद उम्मीद जगी थी कि वहां के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में हिंदुओं को समान अवसर मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। निहित संपत्ति अधिनियम 1974 के तहत अराजकतापूर्ण तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दिया गया। साठ फीसद से अधिक हिंदू भूमिहीन हो गए। भेदभाव का असर सभी क्षेत्रों पर होने लगा। ढाका विश्वविद्यालय में तो पचास हजार छात्रों में हिंदुओं की संख्या मात्र दो हजार रह गई है। बांग्लादेश में साझी संस्कृति और जीवन मूल्यों में सांप्रदायिकता से बिखराव तथा परस्पर कटुता पैदा करने का पहला सफल प्रयोग कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन के जरिए किया। अपना घर संभालकर नहीं रख पाने के कारण यह संभव हो पाया था। इतिहास की इस त्रासद घटना के बावजूद हमने कोई सीख नहीं ली।

भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका तो निभा दी, लेकिन हम भूल गए कि राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक मान्यताओं से नहीं बनता है। संस्कृति उसकी बुनियाद होती है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है, जिसे 98 फीसद लोग बोलते हैं। यह बांग्ला भाषा संस्कृति और विरासत की जीवंत वाहक है। अफ्रीकी चिंतक न्गुगी वा थ्योंगो ने भाषा की इसी क्षमता को किसी समुदाय या राष्ट्र के 'स्व' के विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक माना है। बांग्ला ने अंग्रेजी और उर्दू दोनों के बांग्लादेश में प्रसार को रोक दिया। वहां साझी संस्कृति का एक आयाम राष्ट्रगान 'अमार सोनार बांग्ला' है, जिसे रवींद्रनाथ ठाकुर ने वर्ष 1905 में लिखा था। वहां सरकारी कार्यक्रमों में रवींद्र संगीत का उपयोग होता है। बांग्लादेश का सबसे पुराना जगन्नाथ विश्वविद्यालय है, जो 1858 में स्कूल के रूप में स्थापित हुआ था। कट्टरपंथियों को मालूम है कि इन सब पर चोट से बांग्लादेश की पहचान मिट जाएगी। इसलिए वे सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार करने की बजाय हिंदुओं के अस्तित्व को निशाना बना रहे हैं।

बांग्लादेश और पाकिस्तानी राज्यों का सांप्रदायिक आचरण नेहरू-लियाकत समझौते को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देता है। डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना राजनीतिक बलिदान इसी समझौते के विरोध में दिया था। इतिहास ने उनके कदम को सत्य साबित किया है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर बांग्लादेश की स्थिति को बदलने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई ही तात्कालिक रास्ता है। मगर इसका एक और आयाम भी है। बांग्लादेश में हिंदू मिशन की अहम भूमिका होती है। यह मिशन बंगाली अस्मिता को बढ़ाने वाला होना चाहिए था। इस सांस्कृतिक कूटनीति से ही इस्लामिक कट्टरपंथियों से सामाजिक वैधानिकता छीनी जा सकती थी। बंगाली रंगकर्मी, साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार आदि की भूमिका का उपयोग अहम था। इस पर कभी गंभीर मंथन या प्रयास हुआ ही नहीं। कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना तो तात्कालिक आवश्यकता है, मगर बंगाली अस्मिता को समृद्ध करने की योजना को गैर-राजनीतिक एवं गैर सांप्रदायिक तरीके से लागू करना दीर्घकालिक समाधान है। समय के साथ सोच में संशोधन ही संकल्पित लक्ष्य तक पहुंचता है। बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वास्तव में भारत की उपराष्ट्रीयता है। मगर भारत की धर्मनिरपेक्षवादी राजनीति हमारी अपनी संस्कृति और दर्शन का खंडित रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है, जो हमारी भूमिका में नैतिक पक्ष को धूमिल कर देता है। अतः चुनौती घर को संवारने की और बाहर अपनी संस्कृति की ताकत दिखाने की है।

Jansatta Page No-16

नफरत के विरुद्ध

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कुछ झांकियां दिखने लगी हैं उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। पिछले सप्ताह जैसे-जैसे क्रिसमस करीब आया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 'सिपाही' फैल गए। जिन मालों के बाहर क्रिसमस की सजावट की गई थी, उनके सामने ये 'सिपाही' प्रकट हुए तोड़फोड़ करने। जिन स्थलों पर ईसाई लोग इकट्ठा हुए थे ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने वहां भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पहुंच गए लोगों को टोकने।

इन हरकतों के वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे। जबलपुर के एक गिरिजाघर में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दिखीं एक दिव्यांग महिला को डांटती हुईं। विधायक गुस्से में चिल्ला रही थीं यह कहते हुए कि धर्मांतरण नहीं होने देंगी। दिल्ली से एक वीडियो दिखा, जिसमें कुछ बच्चे सेंटा क्लाज की लाल टोपी पहने हुए हैं। उनको पकड़ कर जबरदस्ती टोपियां उतारते दिखे हिंदुत्व के 'सिपाही' यह कहते हुए कि 'क्रिसमस मनाना है, तो अपने घरों में जाकर मनाएं'। अनुमान है कि ऐसी कोई साठ से लेकर सौ घटनाएं हुईं और तकरीबन सारी हुईं भाजपा शासित राज्यों में। एक भी घटना के बाद न किसी को दंडित किया गया और न ही किसी मुख्यमंत्री ने अपनी आवाज ऊंची करके इन हिंदुत्व के सिपाहियों को टोका। ईसाइयों की आबादी भारत में दो फीसद से भी कम है, लेकिन आज के 'न्यू इंडिया' में इनको क्रिसमस भी नहीं मनाने दिया जा रहा है, बावजूद इसके कि भारत का संविधान इजाजत देता है धार्मिक आजादी की।

हिंदू राष्ट्र की मजबूत जड़ें दिखती हैं अगर किसी राज्य में, तो वह है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के शासन में एक कानून पारित किया गया है, जिसके तहत रिश्वत या शादी करके किसी का धर्मांतरण करना गंभीर अपराध है। इसकी सजा है सात साल जेल। नतीजा यह कि सौ से ज्यादा ईसाई लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं 'जबरदस्ती धर्मांतरण' करने की सजा भुगतते हुए। समस्या यह है कि साबित करना बहुत मुश्किल है कि धर्मांतरण जबरदस्ती किसी का हुआ है या उनकी मर्जी से। मगर कानून इतना कड़ा है अब कि किसी को भी जेल भेजा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अजीब हो गई है कि एक तरफ धर्मांतरण को गंभीर अपराध माना जाता है और दूसरी तरफ हत्या तथा बलात्कार को इतना गंभीर अपराध नहीं! इसलिए योगी सरकार की कोशिश थी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेना, जिन्होंने मोहम्मद अखलाक को पीट-पीट कर मार डाला था बिसाहड़ा गांव में दस साल पहले। हिंसक भीड़ ने उसको और उसके बेटे को घर के अंदर से घसीट कर सड़क पर मारा इस शक पर कि उन्होंने अपने फ्रिज में प्रतिबंधित मांस रखा हुआ था। कानून को हाथ में लेकर हत्या करने की यह पहली घटना थी मोदी के राज में। भीड़ में से अठारह लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जो सब जमानत पर हैं। पूरी तरह रिहा हो जाते आज अगर अदालत ने दखल देकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को पलट न दिया होता।

पिछले सप्ताह कुलदीप सिंह सेंगर की सजा कम की दिल्ली की एक अदालत ने। भाजपा के इस विधायक को उम्रकैद की सजा दी गई थी 2017 में एक नाबालिग बच्ची से उन्नाव में बलात्कार करने के लिए। दिल्ली की अदालत ने कम की सजा इस आधार पर कि पाक्सो के तहत विधायक को सरकारी अधिकारी नहीं माना जा सकता है। सेंगर जेल में ही रहेगा इसलिए कि जिस बच्ची का बलात्कार किया था उसने, उसके पिता की हत्या भी की थी। पिछले सप्ताह राहुल गांधी से मिल कर इस बच्ची और उसकी मां ने किसी कांग्रेस शासित राज्य में बसाने की गुहार लगाई थी। वह पीड़ित अब शादीशुदा है, लेकिन उसने बयान दिया कि जब उसने सेंगर की सजा कम किए जाने की खबर सुनी, तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया।

योगी आदित्यनाथ गर्व से अपने आपको बुलडोजर बाबा कहते हैं, लेकिन उनके बुलडोजर कभी हिंदू अपराधियों के घर तोड़ने नहीं पहुंचते हैं। मुसलमानों के घर टूटते हैं बिना उनके अपराध को किसी अदालत में साबित किए हुए। हिंदुओं को रिहा किया जाता है, तब भी जब उनके खिलाफ अदालतों में फैसले सुनाए जाते हैं। क्या ऐसी उल्टी-पुल्टी होगी हिंदू राष्ट्र में कानून प्रणाली? क्या धर्म को देख कर जेल भेजे जाएंगे लोग? क्या धर्म को देख कर बुलडोजर पहुंचेंगे लोगों के घर तोड़ने बावजूद इसके कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'बुलडोजर न्याय' को गलत कहा है?

कौन जाने कि कभी पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, लेकिन अभी से मालूम हो गया है कि ऐसे राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं को अव्वल दर्जे का नागरिक माना जाएगा। अभी से मालूम होने लगा है कि धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की कोई जगह नहीं होगी हिंदू राष्ट्र में। कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान के लिए इस हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं होने वाली है और ऐसा अगर होता है कभी, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर उतनी ही अराजकता देखने को मिलेगी जो आज दिखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान में।

इन देशों का नाम आ ही गया है, तो क्यों न संघ परिवार से यह भी पूछा जाए कि जब आप अखंड भारत की बातें करते है, क्या याद यह नहीं रहता कि भारत अगर अखंड होता तो उसमें मुसलिम आबादी हिंदुओं से अधिक न होती? सवाल महत्त्वपूर्ण है इसलिए कि लगता है कि हिंदुत्व के इन पहरेदारों ने गहराई से सोच कर अपनी विचारधारा नहीं तैयार की है। तैयार की गई है नफरत को आधार बना कर जो अक्सर कमजोर आधार साबित होता है।

> अभी से मालूम होने लगा है कि धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की कोई जगह नहीं होगी हिंदू राष्ट्र में। कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान के लिए इस हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं होने वाली है और ऐसा अगर होता है कभी, तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत के अंदर उतनी ही अराजकता देखने को मिलेगी जो आज दिखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान में।

Jansatta Page No-16

व्यापार समझौतों के समांतर

प्रसंगवश

पीएस वोहरा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी शुल्क नीतियों ने पूरे विश्व को दुविधा में डाला हुआ है और भारत इस पक्ष पर शुरू से ही आर्थिक संकट में है, क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत के साथ जानबूझ कर एकतरफा पक्षपात किया जा रहा है। इन सबके बीच भारतीय रुपया डालर की तुलना में लगातार कमजोर होता जा रहा है। दरअसल, डालर का ऐतिहासिक स्तर 91 रुपए पर पहुंच जाना भी आर्थिक संकट का प्रतीक है।

वर्ष 2025, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त व्यापार समझौते के आधार पर कई नए आयाम देकर गया है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से तीन मुक्त व्यापार समझौतों को अपनी झोली में डाला है। सबसे पहले, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान पिछले चार वर्षों से हो रही वार्ता के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद दिसंबर में भारत ने इस पक्ष पर तेजी से आगे बढ़ते हुए तीसरे सप्ताह में दो देश, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ ये समझौते किए। न्यूजीलैंड के साथ हुआ समझौता तीव्र गति से आगे बढ़ा और मात्र नौ महीने के समय में ही इस पर आपसी सहमति बन गई। 22 दिसंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने टेलीफोन वार्ता पर इसे सहमति प्रदान कर दी। वहीं ओमान के साथ समझौते के लिए बीते 18 दिसंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ओमान में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए। पहले से ही भारत इस पक्ष पर मारीशस, दुबई, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एफटीए (फ्री-ट्रेड-एग्रीमेंट) कर चुका है।

सहमति का लक्ष्य

मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है, जिसमें देश वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को प्रभावित करने वाले कुछ दायित्वों, निवेशकों के संरक्षण और बौद्धिक संपदा के अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपसी सहमति बनाते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार की सहमति का मकसद आपसी व्यापारिक लेन-देन पर लगने वाले विभिन्न करों की दरों को या तो कम करना होता है या पूरी तरह खत्म करना, ताकि वित्तीय मुनाफा बढ़ सके। अन्य मकसद दोनों देशों के बीच नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और वित्तीय निवेश के विभिन्न अवसर को पैदा करना होता है। भारत इस पक्ष पर तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है और उसका यह रुख विभिन्न मुल्कों को अचंभित और चिंतित कर रहा है। यकीनन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी शुल्क नीतियों ने पूरे विश्व को दुविधा में डाला हुआ है और भारत इस पक्ष पर शुरू से ही आर्थिक संकट में है, क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत के साथ जानबूझ कर एकतरफा तौर पर पक्षपात किया जा रहा है। इन सबके बीच भारतीय रुपया डालर की तुलना में लगातार कमजोर होता जा रहा है। दरअसल, डालर का ऐतिहासिक स्तर 91 रुपए पर पहुंच जाना भी आर्थिक संकट का प्रतीक है। इन सबके बीच भारत सरकार द्वारा विश्व के कई विकसित मुल्कों के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को एफटीए के माध्यम से बढ़ाना एक अच्छा कूटनीतिक कदम है और मजबूत आर्थिक नीति भी।

हित का प्रश्न

इन तीनों मुख्य समझौतों पर अगर भारतीय पक्ष की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापारिक लेन-देन में भारत मुनाफे में रहता है। चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर, 2025 तक के आंकड़ों के तहत ब्रिटेन ने भारत को 19 बिलियन पाउंड के निर्यात किए, वहीं भारत से उसने करीब 28 बिलियन पाउंड के बराबर आयात किए। ब्रिटेन के लिए भारत बहुत महत्त्वपूर्ण इसलिए भी है कि वह उसका दसवां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक साझेदार है। हालांकि ब्रिटेन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र तीन फीसद के आसपास ही है। वहीं भारत के पक्ष से भी ब्रिटेन इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अमेरिका और चीन पर भारत की निर्भरता कुछ कम होती है। भारत मुख्य रूप से इंग्लैंड से सोना, लोहा, अल्यूमिनियम, शराब और विभिन्न कार आयात करता है। इसलिए संभव है कि करों की दर में कमी से इसका प्रत्यक्ष फायदा उपभोक्ता को होगा और कच्चे माल के मूल्यों में कमी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा, भारत ब्रिटेन में कपड़ों की आपूर्ति में विश्व में चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है और इस समझौते के बाद भारत की साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे भारत के कपड़ा उद्योग को भी बहुत अधिक मुनाफा होगा।

संतुलन की कसौटी

ओमान के साथ पारस्परिक लेनदेन में भारत घाटे में रहता है और वर्तमान में यह तकरीबन दो बिलियन अमेरिकी डालर के आसपास है। अक्तूबर, 2025 के आंकड़ों के आधार पर ओमान ने भारत को 628 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर निर्यात किया, वहीं भारत से मात्र लगभग 340 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर ही खरीदा है। ओमान के साथ किया गया मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में और उनके मूल्यों को घरेलू बाजार में नियंत्रित करने में एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है। वहीं दोनों देशों की कर की दरों की समाप्ति पर आपसी सहमति से भारत के चावल उद्योग को इससे बहुत अधिक मुनाफा मिलेगा। ओमान में करीब आठ लाख भारतीय रहते हैं और उनकी व्यक्तिगत आय में भी इस समझौते से बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत को वार्षिक स्तर पर करीब दो बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर 'रेमिटेंस' की प्राप्ति की आशा है।

न्यूजीलैंड और भारत के आपसी लेन-देन में भारत फायदे में रहता है। जून, 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने उसे जहां तकरीबन 3.6B बिलियन अमेरिकी डालर निर्यात किए हैं, वहीं उससे मात्र 1.79 बिलियन डालर के आसपास ही आयात किए। भारत-न्यूजीलैंड से मुख्य तौर पर डेयरी उत्पाद, ऊन इत्यादि खरीदता है और न्यूजीलैंड को मुख्य रूप से दवाइयां और रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय करता है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता मुख्य रूप से भारत के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आइटी कंपनी, पर्यटन, बैंकिंग क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि को वहां विस्तार करने का मौका देगा और इसके माध्यम से विभिन्न भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार की संभावनाएं न्यूजीलैंड में खुलेंगी। वर्तमान समय में न्यूजीलैंड में तकरीबन तीन लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का पांच फीसद है।

डालर का बोझ

अभी यह समझना बाकी है कि क्या भारत इन सभी देशों के साथ हो रहे आपसी लेन-देन को डालर से दूर रखकर कर सकता है। अगर ऐसा संभव होता है, तो यकीनन डालर की तुलना में भारतीय रुपए में हो रही कमजोरी पर लगाम लग सकती है। अमेरिकी शुल्क की दरों के कारण मई से लेकर नवंबर तक भारत का अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग 21 फीसद की कमी आ चुकी है और इससे उबरने के लिए भारत में घरेलू स्तर पर जीएसटी में कटौती पहले से ही कर दी गई। फिर भी भारत को एफटीए के पक्ष पर सकारात्मक ही देखा जाना चाहिए।

Jansatta Page No-16

बांग्लादेश से सतर्क रहने का समय

संजय गुप्त

भारत को बांग्लादेश के हालात पर गहरी निगाह रखने के साथ ही वहां चुनाव बाद बनने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए आपको आप को तैयार रखना होगा

बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छेड़े गए छात्र आंदोलन से अशांति और अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस आंदोलन के चलते शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा और उन्हें जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके तख्तापलट के बाद सेना के हस्तक्षेप से वहां बनी अंतरिम सरकार की कमान जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने संभाली तो माना यह गया था कि वे अशांति और अस्थिरता दूर कर वहां बन रहे भारत विरोधी माहौल पर भी लगाम लगाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 16 माह बाद भी बांग्लादेश अशांत एवं अस्थिर है और वहां भारत विरोधी तत्व भी बेलगाम हैं। पिछले दिनों वहां जब एक कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी गई तो यह अफवाह फैलाई गई कि उसका हत्यारा भारत भाग गया है। उसके साथ-साथ शेख हसीना को भी सौंपने की मांग कर वहां नए सिरे से भारत विरोधी माहौल बनाया जाने लगा। इसी माहौल में वहां एक हिंदू युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को सबके सामने जला दिया गया। इसके बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि छात्र नेता के हत्यारे के भारत भाग जाने की कहीं कोई सूचना नहीं। इसके बाद भी वहां भारत विरोधी तत्व उत्पात मचा रहे हैं। वे भारत के उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिश करने के साथ हिंदुओं पर हमले करने में लगे हुए हैं, जबकि हादी के भाई ने उसकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार को ही कठघरे में खड़ा किया है। बीते दिनों वहां एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। इसके अलावा हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। इसी तरह की घटनाएं तब भी हुई थीं, जब शेख हसीना का तख्तापलटा गया था।

भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच वहां के सबसे बड़े राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान जिया का 17 साल बाद लंदन से लौटना एक बड़ा घटनाक्रम है। वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। इस समय खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में हैं। यदि फरवरी में होने वाले आम चुनावों में बीएनपी जीत हासिल करती है तो तारिक रहमान देश की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन इन चुनावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कहना कठिन है। इसका बड़ा कारण यह है कि अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर

अवधेश राजपूत

उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, उस जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, जिस पर शेख हसीना ने इसलिए प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि वह पाकिस्तान समर्थक है। जमात ने बांग्लादेश की लड़ाई के समय पाकिस्तान का साथ दिया था। जमाते इस्लामी के साथ ही बांग्लादेश में अन्य ऐसे कट्टरपंथी तत्व बेलगाम हैं, जो भारत विरोध के साथ हिंदुओं पर दमन के लिए कुख्यात हैं। मोहम्मद यूनुस उन पर लगाम लगाने की कहीं कोई कोशिश करते दिख नहीं दिख रहे हैं।

बांग्लादेश का जन्म भारत की मदद से हुआ था। वहां लंबे समय सत्ता में रहीं शेख हसीना भारत की मित्र थीं। उनके समय में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई, लेकिन अब वहां भारत विरोधी माहौल है। इसका बड़ा कारण मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से भारत विरोधी तत्वों की अनदेखी किया जाना है। वे न तो कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और न ही भारत से संबंध सुधारने में। ऐसा लगता है कि शेख हसीना के प्रति उनकी नाराजगी भारत विरोध में तब्दील हो गई है। वे भारत की चिंताओं का समाधान करने के बजाय उन्हें बढ़ाने का काम करते दिख रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत की चिंता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस उस पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसने वहां के लोगों पर कहर ढाया था। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वे भारत को चिढ़ाने के लिए ही पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं।

बांग्लादेश में केवल पाकिस्तान का ही हस्तक्षेप बढ़ता नहीं दिख रहा, चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ चीन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके रवैए से लगता है भारत से दोस्ती उन्हें पसंद नहीं। भारत से संबंध सुधारने में उनकी अनिच्छा से प्रतीति होती है कि वे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय ताकतों को भी अवसर दे रहे हैं। ध्यान रहे शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के समय पश्चिमी ताकतों का हाथ देखा गया था। सच जो हो, भारत के लिए यह ठीक नहीं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय ताकतों की भी भूमिका बढ़ती दिख रही है।

भारत को न केवल बांग्लादेश में खतरे का सामना कर रहे हिंदुओं के बारे में सोचना होगा, बल्कि इस देश में अपने हितों की रक्षा के लिए भी कूटनीतिक कौशल दिखाना होगा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ने न पाए। भारत को बांग्लादेश के हालात पर गहरी निगाह रखने के साथ वहां चुनाव बाद बनने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। कहना कठिन है कि चुनाव में क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लोकतंत्र के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर जाता हुआ दिख रहा है। जैसे वहां जो सत्ता में आ जाता है, वह अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन में जुट जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी होता है। पिछले चुनाव में शेख हसीना ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थीं, जिससे खालिदा जिया को चुनावों का बहिष्कार करने के लिए विवश होना पड़ा था। अब शेख हसीना की पार्टी चाह कर भी चुनाव नहीं लड़ सकती। इन स्थितियों में भारत को बांग्लादेश संबंधी अपनी कूटनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। वास्तव में बांग्लादेश हो या अन्य कोई देश, भारत को किसी एक पक्ष अथवा राजनीतिक ताकत के प्रति ही निर्भर रहने से बचना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना होगा कि उसके पड़ोस में लोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिले।

response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

शुक्ल पक्ष

खेमेबंदी की मजबूत दीवार में एक खुली खिड़की

भुनाना हिंदी की सबसे सक्रिय क्रिया है। अमिताभ बच्चन मार्का फिल्म की तरह हर साहित्यकार इस तरह के सवाल का सामना करता है कि तुम्हारे पास राजनीति में भुनाने के लिए क्या है? यही सवाल 'लगभग जयहिंद' के कवि से पूछा गया था। शिल्प, भाव, शब्द को लेकर लग रहा था कि यह रचानाकार नए औजारों से लैस है। या तो इधर या उधर वाली साहित्यिक सत्ता ने पूछा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता कहां है? विनोद कुमार शुक्ल का साहित्यिक किरदार पूछ बैठा, क्या जिंदगी जीते रहना काफी नहीं है? शुक्ल ने साहित्य में ऐसे मध्य-वर्ग को चुना, जो राजनीतिक चश्मे के हिसाब से सबसे निष्क्रिय व बेकार था। जब प्रतिबद्धताओं का प्रदर्शन न हो तो साहित्य कैसा! साहित्य में हताश इस आम आदमी की तरफ शुक्ल ने हाथ बढ़ाया। हताश आदमी जब इस धीरे बोलने, धीरे चलने वाले लेखक के साथ आगे बढ़ा तो साहित्य के शुक्ल-पक्ष में एक जादुई यथार्थ का जन्म हुआ। विनोद कुमार शुक्ल के निधन के बाद हिंदी साहित्य में शुक्ल-पक्ष की अमरता को समझने की कोशिश करता सरोकार।

जनसत्ता सरोकार

बीसवीं सदी में प्रेमचंद ने साहित्य के बारे में जो कहा, उसे आगे के लिए साहित्य की शास्त्रीय परिभाषा माना गया। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। इस खांचे के तहत मुखर राजनीतिक स्वर वाले नायक के बिना साहित्य अधूरा था। दुनिया भर के साहित्य की यही खासियत रही है कि उसने खुद को किसी एक सांचे में समाने से इनकार कर दिया। हिंदी साहित्य में भी ऐसा कई बार हुआ। इस कई में एक नाम विनोद कुमार शुक्ल का भी है। उनके पक्ष पर बात करने से पहले हिंदी फिल्म का एक गीत याद आ रहा है। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं/ कि तू आदमी है अवतार नहीं...। ' साहित्यिक अवतारों की भीड़ में विनोद कुमार शुक्ल आम आदमी की बात कर रहे थे।

विनोद कुमार शुक्ल गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी की राजनीति की एक शैली थी। वैसी शैली, जिसमें बच्चे, युवा, औरत, मर्द सब राजनीतिक हो सकें। खादी के कपड़े पहनना भी राजनीतिक है, तो चरखा कातना भी। शुक्ल का साहित्य भी ऐसे ही खामोशी से आम आदमी को रच रहा था। इस साहित्य का किरदार आपको राजनीतिक नारे लगाते, किसी तरह की मशाल जलाते हुए नहीं दिखेगा। वह एक सामान्य जीवन जी रहा है। इतना सामान्य कि न तो कहीं पर उसका विरोध रेखांकित होगा, न तो उसकी जय या पराजय।

साहित्य का शुक्ल-पक्ष कहता है, 'खुश रहने के लिए बहाने ढूंढ़ने चाहिए और खुश रहना चाहिए। बाद में यही बहाने कारण बन जाते हैं।' वे कहते हैं, 'बहुत से लोग दुख का अभ्यास बचपन से करते हैं। उन्हें इस अभ्यास के लिए मैदान की आवश्यकता नहीं होती है।' शुक्ल के साहित्यिक किरदार किसी तरह के प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं रहे हैं। क्या जीवन को जीते जाना भी किसी तरह का प्रशिक्षण हो सकता है? वह जब मनुष्य को एक इकाई की तरह देखते हैं, उसके ह्रदय यानी अंदरूनी जेब को टटोलते हैं, तो कहते हैं-'झुकने से जैसे जेब से/सिक्का गिर जाता है/ह्रदय से मनुष्यता गिर जाती है।'

साहित्य में शुक्ल पक्ष मध्य-पक्ष है। वह मध्य व्यवस्था के खिलाफ सकल संग्रामी नहीं दिखता है। बिना किसी उत्तेजना के उसका खामोश बैठा रहना बीसवीं सदी की शास्त्रीय परंपरा में अराजनीतिक होना दिख जाता है। अस्मितावाद के चरम काल में वे अपने साथ किसी भी तरह की अस्मिता नहीं ओढ़ते। उनका आम आदमी सोना, उठना, घर के कामकाज, 'बाजार का एक दिन ' जैसी गतिविधियां बिना किसी राजनीतिक उद्घोष के करता है। बेफरियादी साहित्यिक किरदारों को देख कर एकबारगी अचरज होता है कि लेखक ने इन्हें किसी तरह की फरियाद से वंचित क्यों रखा है? शुक्ल तो शिकायत को लेकर इतने निर्मोही हैं कि शोर मचाती उपेक्षा के बीच धीमे-धीमे कहते हैं-

जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे
मैं उनसे मिलने
उनके पास चला जाऊंगा ।
एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी
मेरे घर
नदी जैसे लोगों से मिलने
नदी किनारे जाऊंगा।

> **साहित्य** का शुक्ल-पक्ष कहता है, 'खुश रहने के लिए बहाने ढूंढ़ने चाहिए और खुश रहना चाहिए। बाद में यही बहाने कारण बन जाते हैं।' वे कहते हैं, 'बहुत से लोग दुख का अभ्यास बचपन से करते हैं। उन्हें इस अभ्यास के लिए मैदान की आवश्यकता नहीं होती'

शुक्ल-पक्ष में पाठक साहित्य की सामान्य सी दिखती चीजों के साथ इतने सामान्य तरीके से आगे बढ़ता है कि थोड़ी देर बाद उसकी आम जिंदगी भी उसमें घुल-मिल जाती है। शुक्ल के किरदार अपनी आम जिंदगी को सफल या असफल के खांचे में रखते ही नहीं हैं, तो फिर शर्मिंदा कहां से होंगे। न तो इनकी जिंदगी में प्रतिबद्धताओं के प्रदर्शन का वैसा कोई गर्वोक्ति भरा क्षण आता है कि देखो, यहां से चला था तो यहां पहुंच गया। प्रतिबद्धताओं के चरम की अनुपस्थिति की वजह से पाठक इनके शब्दों से निकल नहीं पाता है, जब निकलता है, तो उसके ऊपर भी एक खामोशी तारी होती है। पाठकों को भी वहां अपने लिए एक ओट दिखता है, कि उसे अब वहां कोई नहीं देखेगा। अपने हिस्से का एकांत पाकर वह निश्चिंत सा हो जाता है।

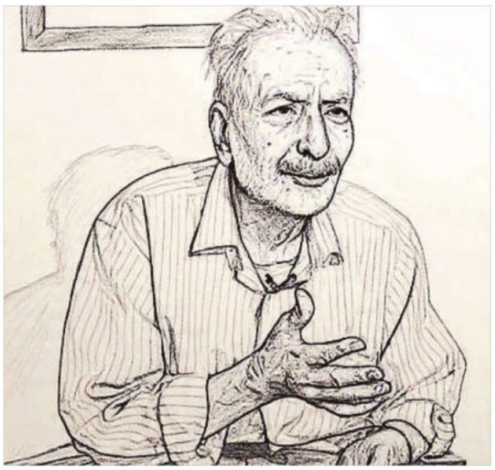

शुक्ल-पक्ष के साहित्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो एक बार शुक्ल का पाठक हुआ, वह उन्हें कभी छोड़ कर नहीं गया। साहित्यकार की तरह उनका पाठक भी बार-बार लौट आता व्यक्ति है। हताशा में बैठे हुए उनके किरदार पाठकों का हाथ पकड़ कर मानो कहते हैं-थोड़ा बैठ जाओ। हताश होना भी एक साहित्यिक क्रिया हो सकती है, यह शुक्ल संभव कर दिखाते हैं। वे कहते हैं-

हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था
व्यक्ति को मैं नहीं जानता था
हताशा को जानता था
इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया
मैंने हाथ बढ़ाया
मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ
मुझे वह नहीं जानता था
मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था
हम दोनों साथ चले
दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे
साथ चलने को जानते थे।

इस तरह साथ चलने लगना ही वह शैली है, जिससे शुक्ल-पक्ष को जादुई यथार्थ का नाम मिला था। कोई उपदेशक भी किसी की हताशा वैसे, खत्म नहीं कर सकता, जैसे उसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ। इस बढ़े हुए हाथ में कोई नाटकीयता नहीं है, बल्कि मनुष्यता की सादगी है। आपने साथ देने के पहले हल्ला मचाया, साथ देने का आडंबर किया, इश्तहार लगाया। अगर एक हताश को अपने जैसा एक हताश हाथ नहीं मिला, तो वह वहीं पर अपनी इति मान लेगा। किसी हताश के लिए इससे बड़ी हताशा और क्या हो सकती है कि उसके आस-पास कहीं हताशा नहीं। क्योंकि आस-पास की हताशा को आडंबरों से ढक दिया गया है। शुक्ल-पक्ष सबसे अराजनीतिक शब्द हताशा को भी उत्साहित कर देता है।

> **साथ** चलने लगना ही वह शैली है, जिससे शुक्ल-पक्ष को जादुई यथार्थ का नाम मिला था। कोई उपदेशक भी किसी की हताशा वैसे, खत्म नहीं कर सकता, जैसे उसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ। इस बढ़े हुए हाथ में कोई नाटकीयता नहीं है।

आज जब वैश्विक स्तर पर भाषाई अस्मिता को लेकर अलगाव चल रहा है, उस समय शुक्ल की कविता भाषाई झगड़े की संकीर्णता से निकलने के लिए प्रेरित करती है। कवि की इच्छा तो देखिए, वह नई भाषा को अपनी मातृभाषा बनाने के लिए बार-बार जन्म लेना चाहते हैं। भाषाई सद्भाव को लेकर यह धरती की निर्दोष अभिव्यक्तियों में से एक है-

अपनी भाषा में शपथ लेता हूं
कि मैं किसी भी भाषा का
अपमान नहीं करूंगा
और मेरी मातृ भाषा
हर जन्म में बदलती रहे
इसके लिए मैं बार-बार
जन्म लेता रहूं-
यह मैं जीव-जगत से कहता हूं
चिड़ियों, पशुओं, कीट-पतंगों से भी।

विनोद कुमार शुक्ल धीरे-धीरे बोलते थे और साहित्य की दुनिया में मध्यवर्गीय साजो-सामान के साथ धीरे-धीरे चले। अपने धीरे-धीरे चलने वाले शब्दों के जादू से उन्होंने अपना एक बड़ा पाठक-वर्ग तैयार किया। उनके शब्दों में मनुष्यता का ऐसा जादू था कि वे कविता, कहानी, उपन्यास के साथ बच्चों के लिए भी लिखने का हौसला जुटा सके।

हिंदी साहित्य में शुक्ल-पक्ष का मध्य-काल इतिहास के घोषित मध्य-काल से अलग है। यहां घर के बर्तन, आम का पेड़, जूते, घर के बाहर की सड़क के बारे में बात हो रही है। विनोद कुमार शुक्ल के जरिए हिंदी साहित्य को ऐसा मध्य-काल मिला जिसे आम पाठक तो बहुत मिले, लेकिन वह अपने किसी भी समकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं रहा। इसकी कोशिश भी नहीं की। दक्षिण उन्हें मजबूरन स्नेह देने में जुट गया क्योंकि वाम की उपेक्षा का आरोप था और वाम की भृकुटि तनी रहती थी कि दक्षिण से जुड़े को क्यों रास आया। इन दोनों अतियों के बीच जो मध्य है, वह शुक्ल के साथ चुपचाप चल पड़ा। लगातार चलती हुई चुप्पी जो राजनीति को अखर रही थी, वह पाठकों का अपना हिस्सा, अपना कोना बन गई।

विनोद कुमार शुक्ल मुक्तिबोध से बहुत प्रभावित थे। शुक्ल राजनांदगांव के थे और मुक्तिबोध वहां के कालेज में पढ़ाने के लिए आए थे। अपनी बातचीत में वे मुक्तिबोध का जिक्र करते रहे हैं। शुक्ल अपनी कविताएं लेकर मुक्तिबोध से मिलने गए थे। मुक्तिबोध, ठहरे मुक्तिबोध। उन्होंने उस उत्साही युवक को समझाया कि कविता लिखना बहुत कठिन काम है। मुक्तिबोध ने उन्हें सलाह दी कि पढ़-लिख कर नौकरी करो और अपनी मां की मदद करो। लेकिन शुक्ल ने हार नहीं मानी और मुक्तिबोध के पास कविताएं लेकर जाते रहे। इन्हीं कोशिशों की बदौलत, बजरिए मुक्तिबोध शुक्ल की कविताएं श्रीकांत वर्मा तक दिल्ली पहुंच गईं और वे पाठकों के हो गए।

विनोद कुमार शुक्ल अब नहीं हैं, तो उनके घर के बाहर की खिड़की के पास बहुत भीड़ है। शुक्ल ने भीड़ की परवाह कब की थी? वे तो खिड़की के बाहर भी अकेले हताश बैठे आदमी को ही पसंद करते थे।

शुक्ल पक्ष की साहित्यिक दीवार की खिड़की के पास शोर बढ़ रहा है। उनके चुप्पा पाठक भी बोलने के लिए निकल पड़े हैं। अब शुक्ल-पक्ष का नया जीवन शुरू हुआ है। देह के पार का जीवन। शब्दों का जीवन। उनके मध्य में फंसा पाठक यह नहीं कह पा रहा-शुक्ल 'कहते थे', वे अभी भी 'कहते हैं', का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेखक का जीवन तो पाठक तय करते हैं-अभी उनके साहित्य को समझने के लिए उम्र पड़ी है। शुक्ल का मूल्यांकन अभी जवां होगा। नई पीढ़ी उनके बारे में नए शब्दों में बात करेगी, जैसे अपने समय में उन्होंने नए शब्द गढ़े थे। भाषा की लड़ाई दो मुल्कों, दो बिरादरियों की ही नहीं, दो पीढ़ियों की भी होती है। शास्त्रीय संगीत सुनने वालों ने सुगम संगीत सुनने वालों को कोसा और अभी उस भाषा को कोसा जा रहा जो नई पीढ़ी के शब्दों से लैस है। इन नए शब्दों पर भी पुरानी दुनिया उसी तरह अचरज करेगी, जैसे शुक्ल के शब्दों पर किया था। इन सबके बीच शुक्ल की आवाज गूंजती रहेगी-

मैं यहीं रहूंगा
लड़ता भिड़ता

मैं अब तक ठगा रहा हूं...

जिस लेखक से उम्मीद की जाती रही थी कि उसका लेखन सत्ता के प्रतिरोध से जरा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए, अगर वह प्रकाशकों के खिलाफ अपना मुखर प्रतिरोध दर्ज कराए तब? ऐसा साहसी कदम वह लेखक उठाए, जिन पर आरोप रहा है कि उनका साहित्य शोषण को लेकर खामोश रहा है। हिंदी साहित्य में यह संभव किया था विनोद कुमार शुक्ल ने।

साहित्य का यह कड़वा सच तब सामने आया जब अभिनेता व रचनाकार मानव कौल विनोद कुमार शुक्ल से मिलने पहुंचे, और उनके साथ हुई बातचीत साझा की। मानव कौल ने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में लिखा था कि पिछले एक साल में छपी तीन किताबों के लिए विनोद कुमार शुक्ल को दो प्रकाशकों की ओर से 6000 और 8000 रुपए मिले। मतलब देश का सबसे बड़ा लेखक साल के 14000 रुपए ही कमा रहा है। कौल का आरोप था कि शुक्ल के पत्र-व्यवहार का प्रकाशक महीनों तक जवाब नहीं देते हैं।

मार्च 2022 में विनोद कुमार शुक्ल ने एक वीडियो में गरिमाहीन रायल्टी को लेकर अपनी व्यथा कही। शुक्ल के इस आरोप से हिंदी साहित्य का बड़ा तबका असहज हो उठा। खासकर हिंदी साहित्य की केंद्रीय परिधि का वह तबका जो इन दोनों प्रकाशन संस्थानों से छपता रहा है, और जो अन्य कारणों से इतना संपन्न है कि रायल्टी के सवाल उठाने को अशोभनीय मानता है।

विनोद कुमार शुक्ल ने वीडियो में रायल्टी को लेकर जो सवाल उठाए, उसमें उनके शब्द थे-मुझे अब तक मालूम नहीं हुआ था कि मैं ठगा रहा हूं। अनुबंधपत्र कानून की भाषा में होते हैं। एकतरफा शर्तें होती हैं, और किताबों को बंधक बना लेती हैं। इस बात का अहसास मुझे बहुत बाद में हुआ, अभी-अभी हुआ। हम तो विश्वास में काम करते हैं। नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी के समय तो ई-बुक और किंडल जैसी चीजें नहीं थीं। पर ये दोनों किताबें ई-बुक, किंडल में हैं। 'कभी के बाद अभी' मेरा कविता संग्रह है। रायल्टी का जो ये जो स्टेटमेंट भेजते हैं तो इस किताब का उस स्टेटमेंट में पिछले कुछ वर्षों से उल्लेख ही नहीं करते हैं। अब चूंकि मैं एक ऐसी उम्र में पहुंच गया हूं, जहां मैं अशक्त हूं और बहुत सी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता, कुछ कर भी नहीं पाता । तो, ये रह जाती हैं और मैं ठगाता रहता हूं।'

रायल्टी पर वीडियो सामने आने के बाद विनोद कुमार शुक्ल के पुत्र शाश्वत शुक्ल ने समाचार एजंसी पीटीआइ से कहा था कि उनके पिता का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उन्होंने वीडियो में ये बातें कहीं जिसे एक स्थानीय मंच ने प्रसारित किया। हालांकि प्रकाशकों ने उनके इस आरोप को खारिज किया था, और इस तरह के 'मीडिया ट्रायल' पर सवाल भी उठाए थे। रायल्टी को लेकर शुक्ल का लगाया आरोप हर उस वक्त सामने आता रहेगा जब-जब लेखक और प्रकाशक के संबंधों पर बात होगी।

हाथी अचानक एक दिन नहीं जा सकता

विनोद कुमार शुक्ल पाठकों के लेखक हैं। यह भी एक विरोधाभास है कि गरिमाहीन रायल्टी को लेकर जिस लेखक ने बहस छेड़ी, उसी लेखक पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि भला तीस लाख की रायल्टी कैसे मिल सकती है? भला इतने कम समय के अंतराल में इतनी किताब कैसे बिक सकती है। यह संभव किया 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' ने। साधारण जीवन को असाधारण तरीके से बरतने के कथा-शिल्प ने रघुवर प्रसाद और सोनसी जैसे आम किरदारों को इतना खास बना दिया कि यह 'जेन जी' की भी पहली पसंद बन गई। रघुवर प्रसाद का हाथी पर कालेज जाना, यथार्थ और कल्पना के बीच का वह पुल है, जिससे पाठक इस पार और उस पार होते रहते हैं। दावा किया गया कि महज 2025 में इस पुस्तक की 87,000 से ज्यादा प्रतियां बिकीं और लेखक को तीस लाख की रायल्टी दी गई।

'दीवार में एक खिड़की रहती थी', को पाठकों ने एक जादुई किताब का दर्जा दे डाला है। इस खिड़की से सूरज, चांद, तालाब, हाथी दिखता है। कठोर यथार्थ के प्रतीक में खिड़की वह कोमल कोना है जो उस पार हर तरह की उम्मीदों को खास रूप-रंग दे जाता है। मध्यवर्गीय अभाव के बीच यह खिड़की वह भाव है जो प्रेम को खोजने का हौसला बनाए रखता है। शुक्ल कहते हैं, 'हाथी अचानक एक दिन नहीं जा सकता, वह जिस दिन जाएगा, रोज की तरह जाएगा।' शुक्ल जी अचानक नहीं गए हैं। वे अपने लिए हाथी जैसी विशालकाय जगह छोड़ गए हैं। पाठकों पर यह जादू तारी रहेगा कि वह जगह कभी खाली नहीं दिखेगी।

जीना इसी का नाम है

हसमुख बाबूभाई पटेल
समाजसेवी

गुजरात के आदिवासी गांवों में सक्रिय एक गांधीवादी

गांधीजी तो हाशिये के लोगों की सुध लेने की बात करते थे, मैं यहां शहर में क्यों हूं? इस बोध ने हसमुखभाई को गुजरात के तब के सबसे पिछड़े जिले बनासकांठा के आदिवासी गांव विरमपुर पहुंचा दिया। यह ऐसा इलाका था, जहां कोई स्कूल न था। लोग पानी की जगह दारू पीते।

महात्मा गांधी को गुजरे 77 साल हो गए। इन बीते वर्षों में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और मिटाने की सियासत खूब हुई, आज भी हो रही है। गांधी की विरासत के दावेदार विपथन के शिकार होते रहे और उनकी शरण में लौटते रहे; तो उनके वजूद को मिटाने की हसरत पालने वालों को बार-बार उनके आगे नत-मस्तक होना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? इनका जवाब हैं हसमुख बाबूभाई पटेल जैसे समाजसेवी! हसमुखभाई पटेल को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल के जमनालाल बजाज सम्मान से नवाजा गया है।

देश को आजाद हुए तब कुछ ही साल हुए थे। अहमदाबाद के करीब बसे एक छोटे से गांव में बेहद साधारण परिवार में हसमुखभाई पटेल पैदा हुए। पिता के पास थोड़ी जमीन और एक छोटी सी दुकान थी, इसी से परिवार का गुजारा चलता था। माता-पिता बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे, पर उनकी इच्छा थी कि वे अपने तीनों बच्चों को पढ़ाएं-लिखाएं। वे जानते थे कि शिक्षा के बगैर उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे और अगर वे पिछड़ गए, तो पटेल परिवार भी आगे न जा सकेगा। चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और तीन-तीन बच्चों की शिक्षा का सवाल था, लिहाजा गांव के स्कूल में ही पिता ने अपने दोनों बेटों और बेटी का दाखिला करा दिया।

प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा जब पूरी हो गई, तब आगे की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद ही विकल्प रह गया था। शहर में तीन-तीन बच्चों को पढ़ाना परिवार के लिए आसान न था, मगर माता-पिता ने अपना प्रगतिशील नजरिया नहीं त्यागा। हर कष्ट उठाकर भी उन्होंने तीनों बच्चों को अहमदाबाद के छात्रावास में रखा, ताकि कॉलेज की शिक्षा हासिल कर वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। किशोर हसमुखभाई जब शहर के सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंचे, तब उनके लिए वहां का माहौल बिल्कुल अनजाना था, मगर जल्द ही पढ़ाई के अलावा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्हीं दिनों हसमुखभाई गांधीवादियों के संपर्क में आए और अहमदाबाद के गांधी प्रतिष्ठान से उनका रिश्ता बना।

देश के बड़े-बड़े गांधीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता उस आश्रम में आते रहते थे। उनमें से कई को हसमुखभाई ने करीब से देखा-जाना। उन्होंने गांधी का खूब अध्ययन किया। अन्याय का अहिंसक विरोध और रचनात्मक कार्यों से समाज में बदलाव का गांधीवादी नजरिया हसमुखभाई पर तारी होता गया। उन्हीं दिनों गुजरात सरकार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। हसमुखभाई 1974 के उस आंदोलन में कूद पड़े। जाहिर है, उन्हें भी जेल हुई। वह आंदोलन कामयाब रहा। चिमनभाई पटेल सरकार को हटना पड़ा था। इस सफलता ने 19 साल के हसमुखभाई की सोच पर गहरा असर डाला।

इसके तुरंत बाद बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में

'संपूर्ण क्रांति आंदोलन' छिड़ गया था। बहुत तेजी से वह आंदोलन पूरे देश में फैला। चूंकि नवनिर्माण आंदोलन ही उसका प्रेरणादायी था, लिहाजा गुजरात में भी संपूर्ण क्रांति ने जोर पकड़ ली थी। छात्र नेता हसमुखभाई भी उसमें कूद पड़े। आपातकाल लगा, तो उन्हें जिस दिन गिरफ्तार किया गया, उसके अगले ही दिन मंदाकिनी दवे से उनकी शादी होनी थी। मंदा भी जेपी आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की सेनानी थीं, लिहाजा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि वे दोनों विवाहित नहीं थे, इसलिए जेल नियमों के तहत साथ-साथ नहीं रह सकते थे। तब बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नथवानी ने सरकार से कहा कि वह हसमुखभाई और मंदा को एक हफ्ते का फरलो दे, ताकि वे विवाह कर सकें। बाहर निकलकर उन्होंने शादी की और वे फिर जेल लौट गए।

मीसा (कानून) के तहत एक साल जेल में रहने के बाद जब पटेल दंपति बाहर आया, तब तय हुआ कि एक सदस्य परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाएगा और दूसरा समाजसेवा की जिम्मेदारी निभाएगा। गृहस्थी का दायित्व मंदाबेन ने उठाया और समाजसेवा हसमुखभाई के कंधों पर आई। जेल से निकलने के बाद अगले दस वर्षों तक हसमुखभाई अहमदाबाद में स्टडी सर्किल चलाने, पर्यावरण व जन-जागृति के मुद्दों पर युवा प्रशिक्षण शिविर लगाने जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहे। फिर वह मोड़ आया, जब उन्हें लगा कि गांधीजी तो हाशिये के लोगों की सुध लेने की बात करते थे, मैं यहां शहर में क्यों हूं?

इस बोध ने हसमुखभाई को गुजरात के तब के सबसे पिछड़े जिले बनासकांठा के आदिवासी गांव विरमपुर पहुंचा दिया। यह ऐसा इलाका था, जहां कोई स्कूल नहीं था। लोग पानी की जगह दारू पीते। एक-एक महिला के 12 से 20 बच्चे होते, क्योंकि कबाइली मानसिकता के कारण उनको प्रतिशोध लेने के लिए लड़ाकों की जरूरत पड़ती थी। हसमुखभाई ने सबसे पहले खेती, गो-पालन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। फिर बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल की शुरुआत की। आहिस्ता-आहिस्ता चेक डैम (जल-संरक्षण) बनाने, औपचारिक स्कूलों व चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और उनमें मुफ्त सेवाओं ने उन्हें स्थानीय लोगों का गांधी बना दिया।

बीते 40 साल से हाशिये के लोगों के उत्थान में जुटे हसमुखभाई पटेल कितने बड़े बदलाव के सूत्रधार बने, इसे चंद आंकड़ों से समझा जा सकता है। आज गुजरात के वाव-थराद जिले के 450 गांवों में उनके संवेदना सर्वोदय केंद्र काम

उनके संवेदना ट्रस्ट द्वारा निर्मित चेक डैम से 6,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगी है। इससे आदिवासी परिवारों की कमाई बढ़ी है। हजारों गरीब बच्चों को स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिला है। दो लाख से अधिक लोगों ने आश्रम के अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठाया है।

कर रहे हैं। 4,000 लोग शराब से तौबा कर चुके हैं और यह इलाका आज सालाना 70 लाख रुपये की बचत कर रहा है। उनके ट्रस्ट द्वारा निर्मित चेक डैम से 6,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई संभव होने से आदिवासी परिवारों की कमाई बढ़ चुकी है। हजारों गरीब बच्चों को स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिला है। दो लाख से अधिक लोगों ने आश्रम के अस्पतालों व चिकित्सा शिविरों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठाया है।

अब बताइए, गांधी की विरासत को कोई मिटा सकता है?

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह